Carp and Common Carp are produced under this programme.

(e) Out of 28 commercial fish seed farms/hatcheries sanctioned so far, 20 fish seed farms/hatcheries have been completed and the remaining 8 fish seed farms/hatcheries are in various stages of construction.

लघु और कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापनार्थ प्रोत्साहन

*180. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अद्यतन तकनीकी जानकारी के आधार पर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में लघु और कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापनार्थ जानकारी उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में भविष्य में और क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) कुटीर और लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक षि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। इन यूनिटों के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इनमें निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की पहचान करने, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, किराया-खरीद आधार पर मशीनरी आदि की व्यवस्था करने में सहायता देना शामिल है। 19 खाद्य वस्तुओं को लघु क्षेत्र में ही उत्पादन करने के लिए आरक्षित किया गया है।

विविधीकृत समुद्री पदार्थों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग करने में प्रौद्योगिकी का उच्चश्रेणीकरण करने तथा नयी प्रौद्योगिकी लागू करने हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

Complaint lodged by CITU to ILO

1153. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the Centre of Indian Trade Unions (CITU) had lodged a complaint to International Labour Office (Regd. as case No. 1479) in 1988;

(b) if so, what are the details of the complaint; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALVIYA): (a) Yes Sir, the Centre of Indian Trade Union (CITU) had lodged the complaint.

(b) Centre of Indian Trade Unions alleged that the Executive Committee of their affiliated Heavy Water Project Employees Union, which was the majority union, was wrongfully dislodged with the help of the agencies of the Government and a rival union was recognised by the management.

(c) According to the facts available the Heavy Water Project Employees Union got split-up in May 87 and the management extended provisional recognition to the new Executive Committee only after Labour Commissioner had verified that the new Executive was validly elected and also had the majority on its side. The Ministry of Law had endorsed this view.

Central assistance to Andhra Pradesh for Tribal Sub-Plan

1154. SHRI GOPALA RAO, RAO: Will the Minister of WELFARE be

pleased to state:

(a) the details of the amount of special Central assistance provided to Andhra Pradesh for Tribal Sub-Plan during the last three years; and

(b) whether there is any increase over the last year's aid and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WELFARE (DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI): (a) and (b) The following amounts of Special Central Assistance (SCA) to Tribal Sub Plan have been released to Andhra Pradesh over the three years 1986-87 to 1988-89.

(Rs. in lakhs)

Year	SCA
1986-87	850.38
1987-88	1063.23
1988-89	1165.12

The allocation for 1989-90, as of now, is Rs. 1116.00 lakhs.

प्याज उत्पादकों के समक्ष उत्पन्न संकट

1155. **श्री राम जेठमलानी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में प्याज का अधिक उत्पादन होने के कारण प्याज उत्पादकों के समक्ष उत्पन्न संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राहत देने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस राज्य से युक्तिसंगत मूल्य और प्याज खरीदने के लिए कोई व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुए प्रस्ताव पर, केन्द्रीय सरकार ने प्याज उत्पादकों को राहत प्रदान करने हेतु 1989 के मौजूदा विपणन मौसम के दौरान महाराष्ट्र में उचित औसत क्वलिटी की प्याज 60 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की थी । इस योजना के तहत भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने केन्द्रीय नवडल एजेन्सी के रूप में 30,650 मीटरी टन प्याज की खरीद की है ।

Provision of nomination in case of D.D.A. flats

1156. SHRI HARI SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi Development Authority had formulated any rules for nomination, in the event of death of the allottee;

(b) if so, the details thereof and whether any forms are prescribed for the purpose;

(c) if the answer of part (a) above be in the negative, whether the normal laws of succession to properties will apply; and

(d) whether a D.D.A. flat or plot-owner can also execute a will nominating a heir to his or her property?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) A person who takes a DDA flat on hire purchase has been provided the facility of nominating person who can succeed him after h death. No forms have been prescribed for the purpose.

(c) In the absence of a nominatio in the above cases, the transfer tak